# भारतीय समाज में जातिवाद : कारण एवं निवारण

**डॉ0 सूर्यभान रावत**

भारतीय समाज में विभिन्न तरह की सामाजिक समस्यायें विद्यमान रही हैं जिनमें से एक प्रमुख समस्या है जातिवाद। जातिवाद को समझने के लिए जाति को समझना आवश्यक है। जाति सामाजिक स्तरीकरण का एक विशेष प्रारूप है जिसके निर्धारण का आधार जन्म है जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक संरचना को अत्यधिक जटिलता प्रदान करती है। हिन्दू समाज के विकास के प्रारम्भिक चरणों में प्रजातीय विभिन्नता, रूप, रंग एवं व्यवसाय की भिन्नता जाति व्यवस्था के विकास के लिए उत्तरदायी है। समय के अन्तराल में सातवीं शताब्दी के बाद उत्रोत्तर उपजातियों की संख्या बढ़ने लगी तथा इसकी प्रकृति स्थिर हो गई। आज भारतीय समाज में उपजातियों की संख्या लगभग 6000 से भी अधिक है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि भारतीय समाज जैसा विभाजित स्वरूप विश्व के अन्य किसी समाज में नहीं है।

जाति व्यवस्था से जुड़ी एक प्रमुख समस्या है जातिवाद। जातिवाद की भावना व्यक्ति–व्यक्ति के बीच घृणा द्वेष एवं प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। जातिवाद की भावना के विकसित होने से व्यक्ति अपनी ही जाति के हितों को सर्वोपरि समझता है। देश या समाज के हित उसके लिए नगण्य हो जाते है। जातिगत भावना से प्रेरित समस्यायें अपनी ही जाति के हितों के लिए कार्य कर रही है।

जातिगत चेतना ने भारतीय समाज की समतामूलक भावनाओं एवं आधारशिला पर गहरा आघात पहुँचाया है। इससे विचारों की महानता का न तो सूत्रपात होता है और न ही समाज के चतुर्दिक विकास का स्पष्ट चित्र अंकित होता है। यह विचित्र विडम्बना है कि जाति पदक्रम के उच्च शिखर पर बैठा जाति विशेष का कर्णधार अपने निहित स्वार्थो की आड़ में अन्य जाति पदक्रम के सदस्यों के मूल्य भावनाओं के साथ वज्रपात करने के गौरव का अनुभव करता है। जातिगत चेतना लोगों के चरित्र और आचरण को विपरीत रूप से प्रभावित करने का प्रयास करती है। जाति विशेष का सदस्य अपनी जातिगत भावना की संकीर्ण चहारदीवारी से आगे का कुछ नहीं सोच पाता है। ऐसा व्यक्ति राष्ट्र के स्वास्थ्य वैभव एवं प्राप्ति के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं देता है। जातिवादी भावना के कारण समाज के वर्गीकृत लोग एक दूसरे को सन्देह की दृष्टि से देखने लगते है तथा दलित संवर्ग के सदस्यों के साथ अमानवीय व्यवहार करने लगते हैं।

अन्तर्जातीय द्वन्द्व ने समाज की एकता एवं मजबूती का विभिन्न प्रकार से प्रभावित करने का प्रयास किया है। परिणाम स्वरूप सभी प्रकार के राजनीतिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्रिया कलाप देश की समृद्धि में अपना सार्थक योगदान प्रदान नहीं कर सके। भारतीय समाज में प्रत्येक जाति संस्तरण के लोगों की मानसिक शक्ति का उपयोग विकास के सन्दर्भ में न होकर नीचे की जाति के पद क्रम के लोगों को अवनति के पथ पर ढकेलने में अधिक होने लगा है। उच्च जाति पदक्रम के सदस्य निम्न जाति पदक्रम के सदस्यों के चतुर्दिक विकास की बात विवशता के कारण भले ही करें परन्तु उन्हें अन्तर्मन में कभी भी सदभाव एवं स्नेह का पड़ाव प्रदान नहीं करते जिसके वे हकदार हैं। इसका परिणाम यह है कि आज भी दलितों व निम्न जातियों में उच्च जाति के लोगों के प्रति उस संवेदना का संचार नहीं हो सका जिसकी वे अपेक्षा करते हैं।

जातिवाद के विकास में अन्तर्विवाही मान्यता जातिगत प्रतिष्ठा की भावना, जजमानी प्रथा की समाप्ति, जातिगत राजनीति, संस्कृतिकरण जातीय संगठन, औद्योगिक विकास, संचार एवं यातायात के साधनों का विकास इत्यादि रहे हैं।

जाति संघर्ष के प्रारूप एवं परिणामों को देखकर यह आवाज उठने लगी है कि जातिविहीन भारतीय समाज का निर्माण किया जाय। यह कल्पना का विषय तो बन सकता है परन्तु यथार्थ में संभव नहीं है क्योंकि भारतीय समाज पदक्रम के सर्वोच्च पद पर बैठे लोग अपने आधिपत्य को समाप्त होते देखना पसन्द नहीं करते।

जातिवाद के परिणाम अत्यन्त भयावह है यह प्रजातन्त्र के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न करता है। कहने के लिए समानता का नारा लगता है पर व्यवहारिक रूप से जातिवाद का ही डंका बजता रहता है। जातिवाद व्यक्ति के नैतिक पतन के लिए उत्तरदायी है। व्यक्ति जाति हितों में अनैतिक कार्यो को करने से नहीं हिचकता है। नौकरियों में नियुक्ति जाति के आधार पर होती है, जिससे अकुशल श्रम को प्रोत्साहन मिलता है। सामुदायिक भावना का संकुचित रूप दिखलाई पड़ता है जो राष्ट्रीय हितों के लिए घातक है। जातिवाद की भावना गतिशीलता में बाधा उत्पन्न करती है। साथ ही साथ भाई–भतीजावाद को बढ़ावा देती है।

समसामयिक भारतीय समाज में आज भी अधिकांश लोग जातिवाद की बुराइयों से अवगत नहीं हैं। समाज के शिक्षित लोग भी इस तथ्य से अवगत नहीं है कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज के लिए हितकर है अथवा नहीं। भारत विदेशी आक्रमणकारियों से इसलिए परास्त हुआ क्योंकि हम जाति के आधार पर विभाजित थे। यह समाज आर्थिक मोर्चे पर इसलिए कमजोर हुआ क्योंकि जाति आधारित व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य को न तो सम्मान प्राप्त था और न है। कर्मचारी को उसके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत नहीं किया जाता वरन इस प्रकार के निर्णयों में जाति को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। ऐसी स्थिति में एक जाति का दूसरी जाति के साथ मृदुल सम्बन्ध कैसे उत्पन्न हो सकता है?

बौद्विक मोर्चे पर भी भारतीय समाज की स्थिति दयनीय एवं शोचनीय है। बौद्धिक वर्चस्व के ठेकेदार कुछ ही लोग हैं। वे समाज के अधिकाधिक लोगों को इस प्रकार के लाभों से वंचित करना चाहते हैं। समाज के ऐसे सदस्य जो जातिगत संकीर्ण भावना के परिणामस्वरूप अधिकारिक लाभ से वंचित हो जाते हैं। वे समाज के श्रेष्ठ जनों से सकारात्मक सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाते वरन् प्रतिशोध की ज्वाला में झुलसते रहते हैं। इस प्रकार की प्रतिक्रिया से विकास नहीं वरन पतन के द्वार खुलते हैं।

समतामूलक भारतीय समाज व्यवस्था की स्थापना में जाति के आधार पर लोगों के दमन को रोकना आवश्यक है। इस दिशा में समाज सुधारकों ने विशेष प्रयास किया है। शिक्षा के सार्थक प्रसार के कारण प्रत्येक जाति के सदस्यों को विभिन्न प्रकार के रोजगार प्राप्त करने के अवसर मिले हैं। इस सुविधा से जातिगत व्यवसायों से छुटकारा मिला है। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार ने एस0सी0/एस0टी0 तथा ओ0बी0सी0 वर्ग के लोगों को व्यवसाय, शिक्षा, प्रशिक्षण आदि में क्षेत्रों में आरक्षण प्रदान किया है। इस व्यवस्था से भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि जातिवाद भारतीय समाज में एक लाछंन है जो व्यक्ति की सामाजिक चेतना एवं सांस्कृतिक विरासत पर एक ऐसा धब्बा है जिसे मिटाने में पर्याप्त समय लग सकता है। मनोवैज्ञानिक इस सन्दर्भ में इस बात पर बल देते हैं कि व्यक्ति स्वभाव से सामाजिक होता है। वह समानता की चाह रखते हुए भी सभी के साथ मिलकर रहना चाहता है। निम्न जाति के लोगों का उत्थान समय की मांग है। यह तभी सम्भव है जब उनकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाए व उनकी प्रतिभा को विकसित होने के सुअवसर प्रदान किये जायें। यदि देश में स्वस्थ समाज का निर्माण एवं विकास करना है तो इसके लिए जातिवाद की भावना को समाप्त करना आवश्यक है। राष्ट्र के विकास एवं स्वस्थ सामाजिक विकास में जातिवाद की भावना निश्चय ही बाधक है। जातिवाद को दूर करने हतु जाति प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए, अन्तर्जातीय विवाहों को बढ़ावा देना आर्थिक एवं सांस्कृतिक समानता उचित शिक्षा व्यवस्था, जातीय संगठनों पर रोक, जाति राजनीति पर रोक एवं प्रभावशाली व्यावहारिक कानून का निर्माण किया जाना चाहिए।

## सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची

1. प्रो0 ए0एल0 श्रीवास्तव : नई दिशायें– ''भारतीय समाज में जातिवाद– सामाजिक दूरी मिटाने की जरूरत'', हिन्दूस्तान समाचार पत्र, 5 अगस्त 2003.
2. राम आहूजा : सामाजिक समस्यायें, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2007
3. डॉ0 आर0एन0 मुखर्जी एवं भरत अग्रवाल : सामाजिक समस्यायें, विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003
4. नदीम हसनैन : समकालीन भारतीय समाज, भारत बुक सेन्टर 175 अशोक मार्ग, लखनऊ, 2007